अरावली वन-क्षेत्र विस्तार और सघनता में कमी होना

4144. **श्री जने श्वर मिश्री**: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अरावली वन-क्षेत्र की सघनता और विस्तार में लगातार कमी होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो 1952 में अरावली वन-क्षेत्र के विस्तार और सघनता की स्थिति की तुलना में 1998 के दौरान इनकी स्थिति क्या है; और

(ग) अरावली वन-क्षेत्र के विस्तार और सघनता में सुधार लाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा उपग्रह प्रतिविम्बित के ग्रयोग से वन आवपण मील्योकन का कार्य 1987 में शुरू किया गया। अरावली वन क्षेत्र की सघनता तथा विस्तार का मूल्यांकन भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा अलग से नहीं किया गया। अरावली की पहाड़ियां, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तथा दिल्ली राज्यों में फैली हुई है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार, 1989-1997 के मूल्यांकन के मध्य इन राज्यों से वनों की सघनता तथा विस्तार दोनों में ही वृद्धि हुई है। तुलनात्मक वन आ

वरम मूल्यांकन निम्न प्रकार है;

(वर्ग कि.मी.में)

राज्य	1989 मूल्यांकन	1997 मुल्यांकन
हरियाणा	513	604
गुजरात	11,921	12,578
राजस्थान	12,884	13,353
दिल्ली	22	26

(ग) अराली वनों के विस्तार तथा उनकी सघनता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपाय निम्नलिखित हैं:-

(i) राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों तथा भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के माध्यम से वनीकरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

(ii) वनों के विकास के लिए, दो विदेशी सहायता प्राप्त वानिकी परियोजनाएं जो हरीयाणा तथा राजस्थान के अरावली क्षेत्र के भाग में क्रियान्वयनधीन हैं, निम्नलिखित है:-

(क) हरियाणा में अरावली की पहांड़ियों में आम भुमियों का मुन:स्थापन:

यूरोपियन आर्थिक आयोग की सहायता से, इस परियोजना को हरियाणा के चार दक्षिणी जिलों अर्थात् भिवानी, महेन्द्रगढ़, गुड़गांव तथा फरीदाबाद में 1990 से क्रियान्वित किया जा रहे हैं। परियोजना का कुल परिव्यय 48 करोड़ रुपए हैं। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय सुरक्षा तथा अर्द्ध-शुष्क अरावली पहाड़ियों में हरित आवरण की पुन:स्थापनी करना और स्थानीय लोगों की रहन-सहन की दशाओं में सुधार करना है।

(ख) राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों के लिए वानिकीकरण परियोजना

इस परियोजना को, सामुद्र-पार आर्थिक सहयोग निधि जापान के वित्त-पोषण से, राजस्थान सराकर द्वारा 176.69 करोड़ रुपए की कुल लागत से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य, मरुस्थलीकरण को रोकना तथा पुन: वनीकरण के माध्यम से पारिस्थितिकीय स्थिति को बहाल करना तथा स्थानी य आवश्यकताओं की बुर्ति के लिए ईंधन लकड़ी, चारा, इमारती लकड़ी के उत्पादन को बढ़ावा देना भी है। परियोजना को राजर्थान के असावली क्षेत्र के 10 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

(iii) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) तथा 3(2)(v) तथा पर्यावणीय अवक्मण पैदा करने वाली कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाले पर्यावरण (सुरक्षा) नियमावली, 1986 के नियम 5(3)(घ) के तहत, हरियाणा के गुड़गांव तथा राजस्थान के अलवर जिले के पूर्व अनुमति के सिवाय, 7 मई, 1992 को अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

Extent of Forest cover in different States

4145. SHRI K. KALAVENKATA RAO: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether the cstem of forest cover in some of the States is decreasing;